whom highest income tax arrears were pending at the closure of the assessment year 1992-93; and also the amount of arrears against each of them;

(b) what action has been taken by Government for recovery of the arrears till the 31st January, 1993 and the amount actually recovered from each of the defaulters in question; and

(c) whether any date has been fixed for final recovery and if not, whether the same in proposed to be done now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The Assessment Year 1992-93 will close on 31.3.1993. Therefore, it will not be possible to give a reply at this stage.

Credit card facilities by Nationalised Banks

119. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the nationalised banks through which credit card facilities are being made available;

(b) whether Government have issued any guidelines to the banks for issuance of iredit cards;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) if not, what are the reasons therefor;

(e) whether Government intend to frame any guidelines in view of the increasing demand of credit cards so that the consumers may be protected; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that credit card facilities are being provided by the following nationalised banks:—

1. Andhra Bank 2. Bank of Baroda 3. Bank of India 4. Vijaya Bank 5. Canara Bank 6. Allahabad Bank 7. Central Bank of India 8. Syndicate Bank 9. Union Bank of India 10. Corporation Bank 11. Punjab & Sind Bank 12. Dena Bank 13. Indian Overseas Bank 14. Bank of Maharashtra 15. Oriental Bank of Commerce 16. United Bank of India.

(b) to (d) RBI had issued instructions to commercial banks in June 1989 emphasising that the banks should ensure that the credit card business is conducted on sound lines, that they should be selective while issuing credit cards with a view to minimising the incidence of bad debts/frauds, and that they should have a proper machinery for speedy recovery of dues from the card holders The banks were also advised that they should ensure that there is no undue backlog in accumtingIreconciliation of transactions. The banks were further asked by the RBI in November 1990 to prepare comprehensive half-yearly review reports and submit them to their Boards of directors ,with copies to RBI.

(e) and (f) At present, there is no proposal for issue of any fresh guidelines.

सीमेंट संयंत्रों पर लाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें

120. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्रों से 165 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क लेती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कतिपय लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्रों पर 290 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क भी लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ङ) क्या सरकार जिन संयंत्रों से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल किया गया है, उन्हें वह लौटा देगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्टिकल शाफ्ट किल्न अथवा रोटेरी किल्न का प्रयोग करते हुए किसी कारखाने में विनिर्मित सीमेंट पर, जिसकी संस्थापित अथवा लाइसेंससुदा क्षमता विनिर्दिष्ट की गई होती है, 165/- रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता है । अन्य संयंत्रों में विनिर्मित सीमेंट पर 290/- रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता है ।

(ग) वर्टिकल शाफ्ट किल्न अथवा रोटेरी किल्न का प्रयोग करने वाले सीमेंट पर मुख्यत: निम्नलिखित कारणों के आधार पर उत्पाद शुल्क की निम्न दर लागू की गई है :—

(i) दुर्गम्य क्षेत्रों में उपलब्ध चूने के पत्थर के छोटे-छोटे भण्डारों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए;

(ii) चूने के पत्थर के छोटे-छोटे भण्डारों वाले क्षेत्रों में और उनके आस-पास छोटे-छोटे बाजारों की स्थापना करके इसका व्यापार बढ़ाने के लिए ।

(घ) से (च) आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दायरे में लाया जाना

121. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दायरे में लाने का विचार रखती है?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के म्यूचुअल फंडों से संबंधित क्रियाकलापों को सेबी के दायरे में लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Liberalisation of Rules for Attracting Foreign Investment

122. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of the steps Government have taken from time to time to liberalise the rules for attracting foreign investment in the country.

(b) what is the impact of the rules on the inflow of foreign investment during the years 1991 and 1992;

(c) whether Government propose to further liberalise the rules in this regard; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND